

प्रेषक,

डॉ० राकेश कुमार

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

टिहरी गढ़वाल।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून:दिनांक: 4 जनवरी, 2011

विषय:-ग्राम नकोट, तहसील एवं जिला टिहरी में, चम्बा धरासू मोटर मार्ग पर, सीमा सड़क संगठन भारत सरकार को, सेतु निर्माण ईकाई हेतु कुल 3.985 है० भूमि, पट्टे पर आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र सं०-1819/11-28(2009-2010), दिनांक-19.3.2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल, ग्राम नकोट, तहसील एवं जिला टिहरी में, चम्बा धरासू मोटर मार्ग पर, सीमा सड़क संगठन, भारत सरकार को, सेतु निर्माण ईकाई हेतु कुल 3.985 है० भूमि, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा दी गयी सहमति/अनापत्ति एवं शासनादेश संख्या-258/16(1) /73-रा-1 दिनांक-09.05.1984 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या-1695/ 97-1-1(60)/93-रा-1 दिनांक-12.09.1997 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत, वर्तमान प्रचलित बाजार मूल्य एवं उक्त भूमि के मालगुजारी के 100 गुने के बराबर धनराशि एक मुश्त जमा कराये जाने पर, निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन, पट्टे पर, खसरा संख्या-2905 एवं 2895 के अन्तर्गत, आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- (1) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की गयी है।
- (2) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- (3) प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-150/1/85(24)-रा-6 दिनांक-09 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30-30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1-1/2 गुना से कम नहीं होगा।
- (4) प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नहीं रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

- (5) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।
- (6) प्रश्नगत भूमि पर, वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत, नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।
- (7) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों बिन्दु संख्या-1 से 6 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

2- उक्त आदेशों का नियमानुसार तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित कराते हुए, शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति, अनिवार्य रूप से शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

1

(डा० राकेश कुमार)

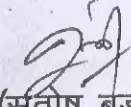
सचिव।

पृ० प० सं०- 12 /संमदिनांकित/2010

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. श्री नारायणा, मेजर, कमान अधिकारी, 1442 सेतु निर्माण ईकाई, द्वारा 56 सेना डाकघर, पिन 931442।
4. निदेशक एन०आई०सी० उत्तराखण्ड सचिवालय।
5. प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(सतीष बडोनी)
अनुसचिव।